ONGC News, 19.09.2021 Print

Oil firms get good response to ethanol procurement tender	Millennium Post	7	Bureau

Oil firms get good response to ethanol procurement tender

NEW DELHI: State-owned fuel retailing firms have received an "overwhelming" response to the tender they floated for buying ethanol for mixing in petrol, a government statement said on Saturday.

"The first Expression of Interest (EOI) for signing long-term agreement with upcoming dedicated ethanol plants for supply of ethanol has received an overwhelming response, with 197 bidders participating in the same," it said without giving details of the quantity ethanol manufacturers have committed to supply.

The EOI was published by Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) on behalf of oil marketing companies on August 27, and it opened on September 17.

"The bids are currently under evaluation," it said.

The oil companies floated the tender to buy ethanol for progressively raising the percentage of ethanol mixed in petrol to 20 per cent (80 per cent petrol, 20 per cent ethanol).

The statement said 173 crore litre ethanol was procured last year and 5 per cent blending was achieved during ethanol supply year(ESY) 2019-20 (December 2019 to November 2020). The target for ongoing year ESY-2020-21 (December 2020 to November 2021) is 325 crore litre which will take the blending to 8.5 per cent. PTI

Indian Oil, Google Pay tie up to make fuel refilling rewarding	Sunday Standard	10	Bureau

Indian Oil, Google Pay tie up to make fuel refilling rewarding

Indian Oil and Google Pay have announced a collaboration to make fuelling more rewarding for Indian Oil and Google Pay customers. For fuel purchases made via Google Pay app at over 30,000 Indian Oil petrol pumps.

सरकारी खजाने का भी इर्धन है पेट्रोल -डीजल	Dainik Jagran	13	Bureau

सरकारी खजाने का भी ईंधन हैं पेट्रोल-डीजल

इसलिए काउंसिल की बैठक में सरकारें जीएसटी में लाने को नहीं हुई राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक के फैसलों से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में राहत की सारी उम्मीदें फिलहाल खत्म हो गई है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना तकरीबन सभी राज्यों की सहमति से लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। वहीं केंद्र के लिए भी पेट्रो राजस्व में कटौती वहन करना मुश्किल है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी राहत की संभावना नहीं है।

शनिवार को नई दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 101.19 रुपये प्रति लीटर थी। इसमें 32.90 रुपया केंद्र के खजाने में जाता है जबकि दिल्ली सरकार 23.35 रुपये प्रति लीटर वसूल रही है। प्रति लीटर डीजल के लिए एक आम ग्राहक 88.62 रुपये दे रहा है जिसमें 31.80 रुपये केंद्र और 12.96 रुपया राज्य सरकार वसूल रही है। केंद्र से जो कर संग्रह किए जाते हैं, उसका भी एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। राज्यों की हिस्सेदारी उनकी तरफ से लगाए अलग-अलग बिक्री कर की दरों से तय होती है। अब दिल्ली में पेट्रोल व डीजल पर पर बिक्री कर की दर क्रमशः 30 फीसद व 16.75 फीसद है। लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33 फीसद का वैट, 4.50 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त वैट व एक फीसद सेस लगाया जाता है। इसी तरह से वहां डीजल पर 22 फीसद वैट, तीन रुपये का अतिरिक्त वैट व एक फीसद टैक्स लगाया जाता है। राजस्थान इन दोनों पर 36 फीसद और 26 फीसद वैट भी लगाता है और भारी भरकम सड़क विकास अधिभार भी वसूलता है। उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 26 फीसद या 18.74 रुपये (दोनों में जो ज्यादा हो) व डीजल पर 17.48 फीसद या 10.41 रुपये प्रति लीटर (जो भी ज्यादा हो) वैट लगाती है।

60 फीसद है राज्यों के कुल बिक्री कर संग्रह में पेट्रो उत्पादों की हिस्सेदारी

तीन दिन पहले आरबीआइ की तरफ से जारी आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले तीन वित्त वर्षों में सभी राज्यों के कुल बिक्री कर व वैट संग्रह में पेट्रोलियम उत्पादों से हासिल राजस्व का हिस्सा क्रमशः 70 फीसद, 64.5 फीसद और 59 फीसद है। वर्ष 2020-21 में राज्यों का कुल बिक्री कर संग्रह 3,42,236 करोड़ रुपये रही है जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 2,02,937 करोड़ यानी 59.3 फीसद रही है। इसके पीछे के दो लगातार वित्त वर्षों में कुल बिक्री कर संग्रह की राशि 3,10,839 करोड़ रुपये 2,88,683 करोड़ रुपये रही जबकि इसमें पेट्रोलियम उत्पादों से वसूल बिक्री कर का हिस्सा क्रमशः 2,00,493 करोड़ रुपये और 2,01,265 करोड़ रुपये रहा।

केंद्र के खजाने में भी पेट्रो उत्पादों से खूब कमाई होती है। वर्ष 2020-21 में 3,71,726 करोड़ रुपये, 2019-20 में 2,33,057 करोड़ रुपये, 2018-19 में 2,14,369 करोड़ का उत्पाद शुल्क सिर्फ पेट्रोल व डीजल से वसूला गया था। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 1.40 रुपये का अतिरिक्त कस्टम डयूटी, 11 रुपये विशेष कस्टम डयूटी, 2.50 रुपये की अन्य डयूटी तथा 18 रुपये की अतिरिक्त कस्टम डयूटी लगाई जाती है।

पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी का सवाल	Amar Ujala	7	Bureau

पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी का सवाल

भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल जैसे देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। जब तक उत्पाद शुल्क सहित अन्य कर पेट्रोल, डीजल पर लगते रहेंगे, इनका मूल्य कम नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए। लेखा महानियंत्रक रिपोर्ट्स के आंकड़ों बताते हैं कि 2021 में अप्रैल से जुलाई तक उत्पाद शुल्क संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। सरकार यदि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो केंद्र और राज्यों के राजस्व में जीडीपी के मात्र 0.4 फीसदी के बराबर ही कमी महसूस होगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में वर्ष 2022 में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जनता के हित के लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने चाहिए। जीएसटी में आने के बाद इस बात की अधिक संभावना है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 75 और 68 रुपये तक पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें किसी बदलाव के लिए जीएसटी पैनल के 75 फीसदी लोगों की मंजूरी जरूरी होती है। कुछ राज्य इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी में आने से उनका राजस्व कम हो सकता है, लेकिन आम जनता का मानना है यदि सरकार पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में कमी करती है, तो उसे महंगाई पर नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट के किराए-भाड़े में कमी आएगी और परिणामस्वरूप तमाम फल, सब्जी और खाद्यान्नों के मूल्यों में भी कुछ कमी आएगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जनहित में डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाकर एक लोकप्रिय निर्णय लेगी और इससे दूरगामी परिणाम सरकार और जनता, दोनों को दिखाई देंगे।

चिट्ठी 2

■ प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, नैनीताल

Ethanol tender big draw	Telegraph	11	Bureau

Ethanol tender a big draw

New Delhi: State-owned fuel retailing firms have received an "overwhelming" response to the tender they floated for buying ethanol for mixing in petrol, a government statement said on Saturday.

"The first Expression of Interest (EoI) for signing long-term agreement with upcoming dedicated ethanol plants for supply of ethanol has received an overwhelming response, with 197 bidders participating in the same," it said without giving details of the quantity ethanol manufacturers have committed to supply.

The EoI was published by Bharat Petroleum Corporation (BPCL) on behalf of oil marketing companies on August 27 and it opened on September 17.

"The bids are currently under evaluation," it said.

The oil companies floated the tender to buy ethanol for progressively raising the percentage of ethanol mixed in petrol to 20 per cent (80 per cent petrol, 20 per cent ethanol).

The statement said 173 crore litre ethanol was procured last year and 5 per cent blending was achieved during ethanol supply year (ESY) 2019-20 (December 2019 to November 2020). The target for ongoing year ESY-2020-21 (December 2020 to November 2021) is 325 crore litre which will take the blending to 8.5 per cent. PTI